

स्टार्टअप इंडिया : नवाचार, उद्यमिता और सतत विकास का अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र

डॉ. खुमेश सिंह ठाकुर*

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) सुभद्रा शर्मा शासकीय कन्या महाविद्यालय, गंजबासौदा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - 'स्टार्टअप इंडिया' भारत सरकार द्वारा 2016 में शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना और एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। 'स्टार्टअप इंडिया' कार्यक्रम भारत में नवाचार, उद्यमिता और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस कार्यक्रम ने स्टार्टअप के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया है, और देश में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। हालांकि, इस कार्यक्रम को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों को दूर करने और 'स्टार्टअप इंडिया' कार्यक्रम को और अधिक सफल बनाने के लिए, सरकार को निरंतर प्रयास करने चाहिए। 'स्टार्टअप इंडिया' कार्यक्रम भारत को वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत, विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसमें युवा आबादी और तकनीकी रूप से कुशल कार्यबल है। इस जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए, 'स्टार्टअप इंडिया' पहल शुरू करने का उद्देश्य, देश में एक मजबूत 'स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र' का निर्माण करना है, जो नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा दे सके। यह कार्यक्रम भारत के आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

प्रस्तावना - स्टार्टअप नये भारत की रीढ़ है। स्टार्टअप का परिस्थितिकी तंत्र नवाचार को प्रोत्साहित कर रहा है और नये युवा उद्यमियों, नये विचार वाले व्यवसायों तथा व्यवसाय करने के नये तरीकों को बढ़ावा दे रहा है तथा उन्हें मजबूत कर रहा है। देश के आर्थिक विकास में स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र की क्षमता और महत्व को पहचानते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान 2016 का अनावरण किया। भारतीय परिस्थितिकी तंत्र का जटिल अवसर स्टार्टअप के मानक जीवन चक्र : विचार, सत्यापन, प्रारंभिक कर्षण और प्रवर्धन में निहित है। इसमें से प्रत्येक चरण में हितधारकों या लाभार्थियों का एक अलग समूह है। तदनुसार स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना के प्रमुख स्तंभों को अलग-अलग दृष्टिकोण के साथ चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने की परिकल्पना की गई थी। कार्य योजना में 'सरलीकरण तथा हैंड होल्डिंग' 'वित्त पोषण सहायता तथा प्रोत्साहन' और 'उद्योग शिक्षा साझेदारी तथा ऊष्मायन' जैसे क्षेत्रों में फैले 19 कार्य शामिल हैं। कार्य योजना 'स्टार्टअप' को एक अलग आर्थिक स्तंभ के रूप में मान्यता देने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाती है। 2016 में लगभग 500 स्टार्टअप से लेकर फरवरी 2023 में 92000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, विश्व स्तर पर प्रसिद्ध भारत के स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) की विकास गाथा और परिस्थितिकी तंत्र तथा समुदाय के संरचित विकास का विषय बन गया है। भारतीय स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र की समावेशिता और विविधता वास्तव में उत्साहजनक है।

स्टार्टअप संस्थाओं की दास्तान का संबंध सिर्फ संख्याओं से नहीं है। यह नये भारत में नूतन अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता की कहानी है। इस नये भारत में नीतियों के केंद्र में एक सुविचारित अर्थनीति है उसमें स्टार्टअप

इंडिया निर्णायक और असाधारण है। स्टार्टअप, उद्यमिता और सीडिंग जैसे शब्दों को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने का श्रेय 16 जनवरी, 2016 को शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया को ही जाता है। यह राष्ट्र के नवोन्मेषको, उद्यमियों और चिंतकों का आह्वान करता है कि वे भारत की संवहनीय आर्थिक विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों के सृजन में नेतृत्वकारी भूमिका संभालें। स्टार्टअप इंडिया भारत के तेज रफतार, सतत नवोन्मेषी और मजबूत उद्यमिता तंत्र की वैश्विक तौर पर प्रसिद्ध यात्रा का प्रतीक बन गया है।

स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य- स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य भारतीय युवाओं में उद्यमशीलता की भावना जगाना और उनमें नवाचारों के प्रति रुचि बढ़ाना है। इसे जनवरी 2016 में स्टार्टअप के लिए अनुकूल परिस्थितिकी तंत्र विकसित करने और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह भारत की सरकारी नीति में अपनाया गया ढांचागत विकास है और इसमें भारत की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और देश के उपेक्षित और वंचित समुदायों को लाभ पहुंचाने की भरपूर क्षमता है।

'स्टार्टअप इंडिया' कार्यक्रम के प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

1. **उद्यमिता को प्रोत्साहित करना:** युवाओं को उद्यमिता करियर के रूप में चुनने के लिए प्रेरित करना।
2. **स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण:** स्टार्टअप के विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाना, जिसमें निवेशक, मेंटर्स, और अन्य हितधारक शामिल हों।
3. **नवाचार को बढ़ावा देना:** नए विचारों और तकनीकों के विकास

को प्रोत्साहित करना।

4. रोजगार सृजन को बढ़ावा देना: स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा करना।

5. आर्थिक विकास को गति देना: स्टार्टअप के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को गति देना।

6. वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना: भारतीय स्टार्टअप को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाना।

स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ- नवाचार किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए आत्मनिर्भर और सतत विकास का आधार है। उद्यमिता वह धुरी है जो नवाचार के जरिए लोगों के जीवन को बदलने में भूमिका निभाती है। हम 'आत्मनिर्भर भारत' होने के अपने मिशन की दिशा में काम करते हैं, ऐसे में नवाचार को बढ़ावा देना और उद्यमियों को सहायता देना, ऐसे दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जो उस गति को निर्धारित करेंगे जिस पर हम विकसित भारत की पटकथा लिखेंगे।

'स्टार्टअप इंडिया' कार्यक्रम छह मुख्य स्तंभों पर आधारित है :

1. सरलीकरण और समर्थन : स्टार्टअप के लिए नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, और उन्हें विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करना।

2. पोषण और वित्तपोषण : स्टार्टअप को धन उपलब्ध कराना, और उन्हें मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करना।

3. उद्योग-अकादमिक साझेदारी और इनक्यूबेशन : उद्योग और अकादमिक संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, और इनक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना करना।

4. स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण : स्टार्टअप के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, जिसमें निवेशक, मेंटर्स, और अन्य हितधारक शामिल हों।

5. जागरूकता और प्रचार : स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना, और लोगों को उद्यमिता के लिए प्रेरित करना।

6. नीतिगत हस्तक्षेप और नियामक सुधार : स्टार्टअप के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए नीतियों और नियमों में सुधार करना।

स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के मुख्य घटक- भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल के पीछे उद्देश्य स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना तथा नवाचार और उद्यमिता के लिए एक मजबूत, समावेशी परिवेश बनाना है। ऐसे परिवेश में सतत आर्थिक विकास को बल देने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने की भी क्षमता है। इस पहल के जरिए सरकार नवाचारों और नये स्वरूपों में स्टार्टअप को सशक्त बनाना चाहती है। इस योजना के अंतर्गत उद्यमियों की मदद करने, स्टार्टअप के लिए मजबूत परिवेश बनाने और भारत को रोजगार-याचक देश की बजाय रोजगार-सर्जक देश बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किये गए हैं। 'स्टार्टअप इंडिया' कार्यक्रम कई प्रमुख घटकों पर आधारित है, जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

1. सरलीकरण और समर्थन:

1. सरलीकृत अनुपालन: स्टार्टअप के लिए नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिससे उन्हें आसानी से व्यवसाय शुरू करने और संचालित करने में मदद मिलती है।

2. स्व-प्रमाणीकरण: स्टार्टअप को कुछ नियमों और विनियमों का स्व-प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी गई है, जिससे अनुपालन बोझ कम

होता है।

3. फास्ट-ट्रैक पेटेंट परीक्षा: स्टार्टअप के लिए पेटेंट आवेदनों की तेजी से जांच की जाती है, जिससे उन्हें अपने नवाचारों को जल्दी से सुरक्षित करने में मदद मिलती है।

4. दिवालियापन कोड में सुधार: स्टार्टअप के लिए दिवालियापन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे उन्हें व्यवसाय विफलता के मामले में आसानी से बाहर निकलने में मदद मिलती है।

2. वित्तपोषण समर्थन:

1. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम : प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप को प्रोटोटाइप विकास, बाजार प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए।

2. क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर स्टार्टअप : स्टार्टअप को ऋण देने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों को क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए।

3. फंड ऑफ फंड्स : निजी इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड में निवेश करके स्टार्टअप के लिए इक्विटी वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए।

4. एंजेल टैक्स छूट: कुछ शर्तों के अधीन स्टार्टअप में निवेश पर एंजेल टैक्स से छूट प्रदान की गई है।

3. इनक्यूबेशन और मेंटरशिप समर्थन:

1. स्टार्टअप इंडिया इनक्यूबेशन सेंटर्स: स्टार्टअप को बुनियादी ढांचा, मार्गदर्शन और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए देश भर में इनक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना की गई है।

2. अटल इनोवेशन मिशन: स्कूलों और कॉलेजों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए।

3. नेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म: स्टार्टअप को अनुभवी मेंटर्स से जोड़ने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है।

4. नवाचार को बढ़ावा देना:

1. स्टार्टअप इंडिया ब्रैंड चौलेंज: नवाचार को बढ़ावा देने और सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए ब्रैंड चौलेंज आयोजित किए जाते हैं।

2. अटल टिकरिंग लैब्स : स्कूलों में छात्रों को नवाचार और समस्या-समाधान कौशल विकसित करने के लिए अटल टिकरिंग लैब्स की स्थापना की गई है।

5. अन्य पहलें :

1. स्टार्टअप इंडिया लर्निंग प्रोग्राम : उद्यमियों को मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम और अन्य संसाधन प्रदान करने के लिए।

2. स्टार्टअप इंडिया शोके : सफल स्टार्टअप को प्रदर्शित करने और उन्हें निवेशकों और अन्य हितधारकों से जोड़ने के लिए।

3. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: अन्य देशों के साथ स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सहयोग स्थापित करना।

स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम का प्रभाव - स्टार्टअप इंडिया का भारत की अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से रोजगार जुटाने तथा आर्थिक प्रगति की दृष्टि से बहुत अहम प्रभाव पड़ा है। सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनियों के राष्ट्रीय संघ (नैसकाम) की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में 2025 तक 5 लाख से ज्यादा नए रोजगार जुटाए जा सकेंगे। इस पहल ने विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित किया है। विश्व में भारत की पताका लहराने के लिए नवोन्मेषी युवा वर्ग की सराहना की जानी चाहिए। उसकी बढौलत ही भारत का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र दुनिया भर में हलचल पैदा

कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा है भारत के स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र का जुनून, सच्चाई और ईमानदारी से भरा होना उसकी ताकत है वह सतत स्व-अन्वेषण करते हुए खुद में सुधार लाकर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। वह लगातार सीखने और खुद में परिवर्तन लाते हुए अपने आप को नई स्थिति के अनुरूप डाल रहा है। 'स्टार्टअप इंडिया' कार्यक्रम ने भारत में स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। यथा -

1. **स्टार्टअप की संख्या में वृद्धि** : भारत में स्टार्टअप की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। डीपीआईआईटी के अनुसार, भारत में 1 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं।
2. **वित्तपोषण में वृद्धि** : स्टार्टअप को मिलने वाले वित्तपोषण में वृद्धि हुई है। वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी निवेश में तेजी आई है।
3. **रोजगार सृजन** : स्टार्टअप ने बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा किए हैं।
4. **नवाचार में वृद्धि** : स्टार्टअप ने विभिन्न क्षेत्रों में नए उत्पादों और सेवाओं का विकास किया है।
5. **आर्थिक विकास में योगदान** : स्टार्टअप ने देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

भारत के स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र में युवा और गतिशील कर्मी विशेष रुचि लेकर शामिल हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी तथा डिजिटलीकरण पर खास ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। भारत की विशाल जनसंख्या और लगातार बढ़ता मध्यम वर्ग स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध कराते हैं और टेक्नोलॉजी तथा डिजिटलकरण से फिनटेक, ई-कॉमर्स और स्वास्थ्य देखरेख जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। अटल नवाचार मिशन और स्मार्ट शहर मिशन जैसी पहलों के माध्यम से सरकार नवाचार प्रोत्साहन पर बोल दे रही है जिससे स्टार्टअप के लिए अधिक अवसर बढ़ रहे हैं।

स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की चुनौतियां - स्टार्टअप इंडिया पहल के महत्वपूर्ण प्रभाव के बावजूद इसे अनेक चुनौतियां और बाधाओं से जूझना पड़ रहा है। स्टार्टअप के सामने एक बड़ी चुनौती फंडिंग तक पहुंच का अभाव है और वह भी खास कर शुरुआती दौर में। एक अन्य चुनौती है स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र में कुशल जनशक्ति का अभाव। अनेक स्टार्टअप अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभवी कुशल कर्मियों की कमी की समस्या झेल रहे हैं। स्टार्टअप पहल में एक कमी यह भी है की मुख्य जोर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप पर ही दिया जाता है। यह तो सही है कि टेक्नोलॉजी स्टार्टअप ने काफी फंडिंग और ध्यान आकर्षित किया है लेकिन स्वास्थ्य-देखरेख, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में बड़ी सफलताएं मिली है एवं इन क्षेत्रों में अभी भी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। 'स्टार्टअप इंडिया' कार्यक्रम ने कई सफलताएं हासिल की हैं, लेकिन इसे अभी भी निम्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, यथा -

1. **धन की कमी** : प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप के लिए धन प्राप्त करना अभी भी मुश्किल है।
2. **मार्गदर्शन का अभाव** : कई स्टार्टअप को अनुभवी मेंटर्स और सलाहकारों की कमी का सामना करना पड़ता है।
3. **जटिल नियामक प्रक्रियाएं** : कुछ नियामक प्रक्रियाएं अभी भी जटिल और समय लेने वाली हैं।
4. **बुनियादी ढांचे की कमी** : कुछ क्षेत्रों में स्टार्टअप के लिए आवश्यक

बुनियादी ढांचे की कमी है।

5. **बाजार तक पहुंच** : सभी स्टार्टअप के लिए अपने उत्पादों और सेवाओं को बाजार में लाना आसान नहीं है।
6. **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल की कमी** : स्टार्टअप को कुशल श्रमशक्ति की कमी का सामना करना पड़ता है।
7. **ग्रामीण क्षेत्रों में कम उद्यमिता** : ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।
8. **महिला उद्यमियों के लिए चुनौतियां** : महिला उद्यमियों को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि वित्तपोषण तक पहुंच और सामाजिक बाधाएं।

इस पहल को कई कानूनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। भारत में स्टार्टअप नियामक व्यवस्था बेहद जटिल है जिससे नियमों का पालन करना काफी कठिन रहता है। स्टार्टअप के नवाचारों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से बौद्धिक संपदा अधिकार के कानूनी प्रारूप को अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है। अमेरिका और जापान की तुलना में भारत का स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र अपेक्षाकृत बाल्यावस्था में ही है और अभी पनप ही रहा है। तो भी हाल के वर्षों में स्टार्टअप इंडिया पहल और उद्यमिता तथा नवाचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अन्य कई पहल करके भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत के स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र में प्रौद्योगिकी और डिजिटलकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। इन प्रयासों के बावजूद भारत के उपेक्षित और वंचित समुदायों के विकास में स्टार्टअप इंडिया का प्रभाव सीमित रहा है भारत के अधिकतर स्टार्टअप शहरी इलाकों में हैं और उनके कर्ताधर्ता संपन्न पृष्ठभूमि वाले लोग ही हैं। देश के वंचित-उपेक्षित समुदायों के सामने आने वाली ढांचागत चुनौतियों पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता, जिनमें सामाजिक भेदभाव शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधाओं तक पहुंच का अभाव और आर्थिक संसाधनों तक सीमित पहुंच जैसी चुनौतियां खास है।

स्टार्टअप इंडिया को सफल बनाने हेतु नीतिगत सिफारिशें - भारत में स्टार्टअप संस्कृति का विकास 21वीं सदी के शुरुआती वर्षों में शुरू हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में कुछ शुरुआती स्टार्टअप ने सफलता हासिल की, जिससे युवा उद्यमियों को प्रेरणा मिली। हालांकि, उस समय स्टार्टअप को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें धन की कमी, मार्गदर्शन का अभाव, और जटिल नियामक प्रक्रियाएं शामिल थीं। 'स्टार्टअप इंडिया' कार्यक्रम इन चुनौतियों को दूर करने और स्टार्टअप के विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए शुरू किया गया था। 'स्टार्टअप इंडिया' कार्यक्रम को और अधिक सफल बनाने के लिए, निम्नलिखित नीतिगत सिफारिशें की जाती हैं :

1. **धन की उपलब्धता बढ़ाना** :
 1. स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी योजनाओं को मजबूत बनाना।
 2. एंजेल निवेशकों और वेंचर कैपिटल फंडों को कर प्रोत्साहन प्रदान करना।
 3. क्राउडफंडिंग को बढ़ावा देना।
 4. सरकारी खरीद में स्टार्टअप को प्राथमिकता देना।
2. **मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करना** :
 1. मेंटरशिप कार्यक्रमों को विस्तारित करना और गुणवत्ता में सुधार करना।
 2. उद्यमिता विकास संस्थानों को मजबूत बनाना।

3. उद्योग-अकादमिक साझेदारी को बढ़ावा देना।
4. स्टार्टअप के लिए ऑनलाइन लर्निंग संसाधनों को विकसित करना।
- 3. नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना:**
 1. अनुपालन बोझ को कम करना।
 2. ऑनलाइन अनुपालन प्रणाली को लागू करना।
 3. निरीक्षणों को कम करना।
 4. विवाद समाधान तंत्र को सरल बनाना।
- 4. बुनियादी ढांचे में सुधार करना:**
 1. इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना।
 2. बिजली आपूर्ति को विश्वसनीय बनाना।
 3. परिवहन अवसंरचना को मजबूत बनाना।
 4. इनक्यूबेशन केंद्रों और स्टार्टअप हब की स्थापना को बढ़ावा देना।
- 5. बाजार तक पहुंच आसान बनाना:**
 1. स्टार्टअप को विपणन और वितरण में सहायता प्रदान करना।
 2. सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर स्टार्टअप को सूचीबद्ध करना।
 3. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्टार्टअप को बढ़ावा देना।
 4. स्टार्टअप के लिए व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन करना।
- 6. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना:**
 1. शिक्षा प्रणाली में उद्यमिता को एकीकृत करना।
 2. कौशल विकास कार्यक्रमों को स्टार्टअप की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना।
 3. तकनीकी शिक्षा संस्थानों को मजबूत बनाना।
 4. स्टार्टअप के लिए इंटरशिप और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
- 7. ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देना:**
 1. ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप हब और इनक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना करना।
 2. ग्रामीण उद्यमियों के लिए विशेष वित्तपोषण योजनाएं शुरू करना।
 3. ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना।
 4. स्थानीय संसाधनों और कौशल का उपयोग करने वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देना।
- 8. महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना :**
 1. महिला उद्यमियों के लिए विशेष वित्तपोषण और मेंटरशिप कार्यक्रम शुरू करना।
 2. महिला उद्यमियों के लिए नेटवर्किंग अवसरों को बढ़ावा देना।
 3. महिला उद्यमियों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
 4. महिला उद्यमियों के लिए अनुकूल नीतियां और विनियम बनाना।
- 9. डेटा-आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देना:**
 1. स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर डेटा एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए एक मजबूत प्रणाली स्थापित करना।
 2. नीतिगत निर्णयों को सूचित करने के लिए डेटा का उपयोग करना।
 3. नियमित रूप से स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की प्रगति का मूल्यांकन करना।
 4. हितधारकों के साथ परामर्श करके नीतियों को लगातार अनुकूलित करना।

निष्कर्ष – हम अपने जीवन, व्यवसाय और सपनों की कहीं ना कहीं से शुरुआत करते हैं। यह अपनी कामनाओं के राह पर चल पड़ने, किसी अनूठे

विचार को सँजोने और फिर उसे साकार करने, राह में आने वाली चुनौतियों का सामना करने और विश्वास के साथ चुने गए लक्ष्य को हासिल करने की यात्रा है। यह ऐसे नवीन समाधानों, उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने की भी यात्रा है। जिनसे अपने परिवेश-समाज को बेहतर बनाने की नई राहें, नये साधन मिले। भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल के पीछे यही विचार है।

इस पहल के उद्देश्य हासिल करने के लिए सरकार ने एक कार्य-योजना बनाई है जिसमें स्टार्टअप परिवेश के सभी पक्षों पर ध्यान दिया जा रहा है। इस परिस्थितिकी तंत्र से स्टार्टअप आंदोलन तेज होगा और टेक्नोलॉजी के साथ-साथ कृषि, निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में भी इसका दायरा बढ़ेगा और इसका फैलाव वर्तमान महानगरों के साथ-साथ दूसरी और तीसरी श्रेणियों के शहरों, उपनगरीय तथा ग्रामीण इलाकों में भी बढ़ेगा। स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत मुख्यतः नये उद्यमों और कारोबारों के इन पक्षों में मदद की जाती है - प्रक्रियाओं को सरल बनाना और इन्हें पूरा करने में मदद करना, नियमों का पालन आसान बनाना, स्टार्टअप के आगे ना बढ़ पाने की स्थितियों में इन्हें छोड़ पाने की आसान प्रक्रियाएँ, कानूनी मदद, पेटेंट आवेदनों का तेजी से निपटान, ज्यादा से ज्यादा जानकारीयें वेबसाइट के जरिए उपलब्ध कराना, धन उपलब्ध कराना और अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन देना, आयकर और कैपिटल गेन में छूट के प्रावधान, स्टार्टअप को ज्यादा धन मुहैया करा पाने के लिए संबंधित फंडों को भी धन देने के लिए एक और फंड (फंडऑफ फंड्स) बनाना और ऋण गारंटी योजना का प्रावधान, नये स्टार्टअप को सहारा दिलाने के लिये इंक्यूबेशन की व्यवस्था, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच भागीदारी, नये इंक्यूबेटर और इनोवेशन लैब्स खोलना, प्रोत्साहन और जानकारी देने के लिए विभिन्न गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन और अनुदान मुहैया कराना है। स्टार्टअप हमारी आम जिंदगी की अनेक समस्याओं के नवीन और टेक्नोलॉजी-आधारित समाधान प्रस्तुत करते हैं। युवाओं में नये तरीके से सोचने और चली आ रही प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं को चुनौती देने की क्षमता होती है। स्टार्टअप हमारे युवाओं की कल्पना और क्षमता को पंख लगा देते हैं ताकि वे नये भारत की विकास-यात्रा में भागीदार बन सकें।

'स्टार्टअप इंडिया' कार्यक्रम भारत में नवाचार, उद्यमिता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कार्यक्रम ने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, लेकिन इसे अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों को दूर करने और 'स्टार्टअप इंडिया' कार्यक्रम को और अधिक सफल बनाने के लिए, सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत को मिलकर काम करना होगा। नीतिगत सिफारिशों को लागू करके, भारत एक मजबूत और जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर सकता है, जो देश के आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया (2016). स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान- https://www.startupindia.gov.in/content/dam/investindia/startupindia/pdfs/Startup_India_Action_Plan.pdf से लिया गया।
2. ऑक्सफैम इंडिया, (2018). माइंड द गैप. द स्टेट ऑफ एंजलायमेंट इन इंडिया- <https://www.oxfamindia.org/sites/default/files/>

- 2018-03/Mind-The-Gap.pdf से लिया गया।
3. नेशनल हैंडिकेप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. (एन.डी.). अबाउट <https://www.nbfcd.nic.in/about-us> से लिया गया।
 4. स्टैंड-अप इंडिया (एन.डी.). अबाउट <https://www.standupmitra.in/about-us>. से लिया गया।
 5. सिंह, एच. (2018). एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स इन इंडिया : चौलेंजेज एंड अपार्च्यूनिटीज। जर्नल ऑफ इनोवेशन इकोनॉमिक्स एंड बेनेजमेंट, 27(1), 41-54, डीओआई: 10.3917/जेआईई.पीआर.1.0027.1
 6. अग्रवाल, आर. और गर्ग, एस. (2018). स्टार्टअप इंडिया: नीति, प्रगति और चुनौतियां. आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 53(12), 35-42
 7. गुप्ता, आर. (2020). स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया: स्टेटस, चौलेंजेज एंड वे फॉरवर्ड. जर्नल ऑफ इनोवेशन इकोनॉमिक्स एंड बेनेजमेंट, 35(1), 11-25. डीओआई: 10.3917/जेआईई.पीआर.1.0035.1
 8. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया (2016)। स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र इन इंडिया: एक्शन प्लान. <https://www.startupindia.gov.in/content/site/en/action.plan.html>.
 9. दास, एस. (2020). भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र: एक सिंहावलोकन. जर्नल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, 29(1), 1-25.
 10. कुमार, ए. और सिंह, पी. (2021). स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम का प्रभाव: एक अनुभवजन्य विश्लेषण. भारतीय आर्थिक समीक्षा, 56(2), 201-225.
 11. ऑक्सफैम इंडिया (2019)। इंडिया इनइक्वैलिटी रिपोर्ट 2018: Widening Gaps. <https://www.oxfamindia.org/sites/default/files/201908/Oxfem-Inequality-Report.2018.pdf> से लिया गया।
 12. मिश्रा, पी. और जैन, वी. (2022). भारत में स्टार्टअप्स के लिए वित्तपोषण चुनौतियां और समाधान. वित्त और अर्थशास्त्र के भारतीय जर्नल, 80(3), 456-475.
 13. शर्मा, आर. और गुप्ता, एस. (2023). भारत में महिला उद्यमिता: चुनौतियां, अवसर और नीतिगत हस्तक्षेप. प्रबंधन अनुसंधान जर्नल, 23(1), 123-145.
 14. चौटर्जी, ए. (2018). स्टार्ट-अप इंडिया ए कांप्रिहेंसिव एनेलिसिस. जर्नल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड सोशल रिसर्च. 7(3), 1-8।
 15. द इकोनॉमिक टाइम्स. (2021). स्टैंडअप इंडिया स्कीम : इलिजिबिलिटी, बेनेफिट्स, इंटरैस्ट रेट, एंड हाऊ टू एप्लाई <https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/sme-sector/stand-up-india-scheme/articleshow/78416343.cms> से लिया गया।
 16. ओईसीडी (OECD) रिपोर्ट (2021): भारत में नवाचार को बढ़ावा देना: नीतिगत सिफारिशें. पेरिस: ओईसीडी प्रकाशन।
 17. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एमपॉवरमेंट, (2021), नेशनल हैंडिकेप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. <https://nhfcd.nic.in/frmSchemeDetails.aspx> से लिया गया।
 18. मिश्रा एस.के. एंड सिन्हा, ए, (2018) स्टार्टअप इंडिया ए बून ऑर बेन फॉर इंडियाज मार्जिनेलाइज्ड कम्यूनिटीज ? जर्नल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन इन एमर्जिंग इकोनॉमिक्स, 4(1), 68-76 से लिया गया।
 19. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) रिपोर्ट (2022): भारत में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्टार्टअप्स की भूमिका. न्यूयॉर्क: यूएनडीपी।
 20. द हिन्दू (2019)। स्टार्टअप इंडिया व्हाई विमेन एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट मेकिंग द कट। <https://www.thehindu.com/business/Industry/start-up-india-why-women-entrepreneurs-are-not-making-the-cut/article28329050> से लिया गया।
 21. गुप्ता, वी एंड जैन, आर. के. (2017)। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनक्लूजिव ग्रोथ इन इंडिया: द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स. जर्नल ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, 8(2), 177-194 से लिया गया।
